



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 11 अक्टूबर, 1993/19 आश्विन, 1915

थ्रम विभाग

आधिसूचना

शिमला-2, 1 अक्टूबर, 1993

संख्या थ्रम(ए) 4-27/93.—भारत के राष्ट्रपति वो यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित अनुसृचित नियोजनों में कार्यरत अकुणज मजदूरों की त्यूनतम मजदूरी 22/- रुपये से 24/- रुपये प्रतिदिन या 660/- रुपये से 720/- रुपये प्रतिमाह पुनरीक्षित कर दी जाए :—

1. कुषि ।
2. सड़क निर्माण या अनुरक्षण तथा भवन किया ।
3. पत्थर तुडाई या पत्थर कर्किंग ।
4. पब्लिक मोटर ट्रांस्पोर्ट ।

5. बन एवं काष्ठ क्रिया ।
6. दुकाने तथा वाणिज्य संस्थान ।
7. रसायन तथा रसायनिक उत्पाद ।
8. इन्जिनियरिंग उद्योगों ।
9. खाद्य एवं पेय पदार्थ ।
10. गलीचा व शाल बुनाई ।
11. वस्त्र एवं हौजरी उद्योगों ।
12. कागज उत्पाद ।
13. हाइट भट्ठा उद्योगों ।
14. लकड़ी पर आधारित तथा फर्नीचर उद्योगों ।
15. चाय बागानों ।
16. विनिर्माण प्रक्रिया जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (के) में परिभ्राष्ट है ।
17. मद्य निर्माण शालाओं, शराब कारखानों और अन्य अनुसंधिक प्रचालनों जैसे बोतलें भरने ।
18. सीमेंट कारखानों तथा सीमेंट से बनने वाले अन्य उत्पाद ।
19. ग्रांरा मशीनों ।
20. निजी शैक्षणिक संस्थानों ।
21. कास्टिंग उद्योगों ।
22. चमड़ा उद्योगों ।
23. इलैक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्रीज ।

2. भारत के राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि उक्त अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत अर्धकुशल, कुशल तथा उच्च कुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दरें 9.09% बढ़ा दी जाए, परन्तु यह 2/- स्थिरे प्रतिदिन से कम न हो ।

3. भारत के राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि जो मजदूर जनजातीय क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में कृषि, सड़क निर्माण और अनुरक्षण, वानिकी तथा निर्माण वाट्ठ, पत्थर क्रसिंग तथा पत्थर तुड़ान के अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत मजदूरों को क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 12½ प्रतिशत की प्रस्तावित पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों के अतिरिक्त और बढ़ीतरी की जाएगी । जो मजदूर सुरागों में कार्यरत है, उन्हें पिछले वर्षों की तरह और 20 प्रतिशत की बढ़ीतरी होगी और इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों व पिछड़े क्षेत्रों में मजदूरी क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 12½ प्रतिशत की बढ़ीतरी की जाएगी ।

4. अतः भारत के राष्ट्रपति, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्सरण में इस प्रस्ताव को उन व्यक्तियों की सुचना के लिए प्रकाशित करते हैं जिनकी उक्त प्रस्ताव से प्रभावित होने की सम्भावना है । उक्त प्रस्ताव पर कई आपत्तियां या सुझाव हों तो उसे श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 वो इस प्रस्ताव के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (अमाधारण) में प्रकाशित होने की तारीख से दो महीनों की अवधि के अवसान से पहले विचार के लिए भेजें ।

5. प्रस्तावित पुनरीक्षित दरें 14-11-1993 से लागू होंगी ।

आदेश द्वारा,

प्रभोद कुमार,
आयुक्त एवं सचिव ।